वर्ष 4 अंक 2 फरवरी 1982 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

19 जनवरी
एक स्मरणीय दिवस

भारत में मजदूर वर्ग संघर्ष के इतिहास में 19 जनवरी 1982 एक स्मरणीय दिवस होगा. इसका महत्व इसमें नहीं है कि हड़ताल में मजदूर वर्ग के कितने प्रतिशत ने भाग लिया, बल्कि यह इस तथ्य में है कि पहली बार समूचे मजदूर वर्ग ने, इंटक के समर्थकों को छोड़कर, राजनीतिक बंधनों को तोड़ दिया और केवल आर्थिक मांगों पर नहीं बल्कि राजनीतिक मांगों, जैसे कीमतवृद्धि व सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ, पर भी एकजुट होकर हड़ताली कार्यवाही की.

हड़ताल ने देश में मजदूर वर्ग आंदोलन को नए आयाम प्रदान किए हैं. किसानों, खेतिहर मजदूरों व समूची जनता के हितों के लिए, मजदूर वर्ग ने सरकार की सांमत-परस्त, एकाधिकार-परस्त व बहुराष्ट्रीय निगम-परस्त, तथा घाटे की अर्थव्यवस्था व मुद्रास्फीति की बुनियादी नीतियों पर चोट की जो आम जनता पर कीमत वृद्धि द्वारा कष्टों की बौछार तथा जनवादी प्रक्रिया की बुनियाद तक को शिथिल करने के लिए जिम्मेदार हैं.

छात्रों, युवकों, महिलाओं, मध्यमवर्गीय कर्मचारियों, गरीब किसानों व खेतिहर मजदूरों ने—सभी ने हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त की. चार जून के बंबई सम्मेलन के संदेश को कार्यवाही में बदला गया और इसने अधिनायकवादी निजाम के खिलाफ वामपंथी व जनवादी विकल्प का रास्ता तैयार किया.

सरकार का हड़ताल तोड़नेवाला रूप

'समाजवाद' की सभी मूर्ख बनाने वाली मीठी मीठी बातों की उपेक्षा कर दी गयी और उस समय इंदिरा निजाम के अधिनायकवादी चरित्र का पर्दाफाश हुआ जब यह हड़तालियों पर जंगली प्रतिशोध की भावना से टूट पड़ा. हड़ताल की पूर्व-संध्या से शुरू होकर 19 जनवरी तक 50 हजार से भी ज्यादा को गिरफ्तार किया गया जिसमें अकेले केरल के 20 हजार शामिल हैं. एकाधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए चौकीदार का काम करते हुए सरकार ने कांग्रेस (आई) व इंटक के गुंडों की मदद से शांतिपूर्ण हड़तालियों को पीटने के लिए, झगड़े व तोड़फोड़ करने के लिए पुलिसबल व समाजविरोधी तत्वों को खुला छोड़ दिया और इस द्वारा गोलीबारी के कारण खेतिहर मजदूरों सहित दस व्यक्तियों की हत्या हुई.

मजदूर वर्ग एकता की छाया सरकार का पीछा करती रही और सरकार ने राज्य सरकारों को गुप्त सरकुलर भेजे कि हड़तालियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए. आकाशवाणी व दूरदर्शन को कहा गया कि तोते की तरह झूठ की यह रट लगाए रखे कि हड़ताल असफल हो गयी. बिहार सरकार ने 'देखते ही गोली मारने' के आदेश जारी कर दिए (ऐसे आदेश एक महीने में दूसरी बार जारी किये गए).

निडर मजदूर

लेकिन सेवा में ब्रेक व वेतन कटौती की धमकियों के बावजूद, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व श्रम मंत्री की धमकियों के बावजूद, एस्मा व एन एस ए को लागू करने तथा नेताओं व कार्यकर्त्ताओं की भारी तादात में गिरफ्तारियों के बावजूद और हजारों की तादात में पुलिस व पैरा-मिलिट्री बल नियुक्त करने के बावजूद एक करोड़ बीस लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. बिहार के मजदूर वर्ग व जनता ने 19 जनवरी को पूर्ण बंद आयोजित करके बिहार सरकार पर तमाचा लगाया. इस तरह का तमाचा केरल में वामपंथी व जनवादी ताकतों ने प्रतिक्रियावादी व अवसरवादी ताकतों को लगाया. वास्तव में यह अल्पमत सरकार के लिए एक सबक था.

केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को वाम मोर्चे द्वारा बंद के आह्वान के खिलाफ चेतावनी दी. यहां तक कि हाई कोर्ट के न्यायधीश ने निंदा की. लेकिन मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु ने यह घोषणा ठीक ही की कि न तो केंद्र सरकार और न ही अदालतें मजदूर वर्ग के उसके जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष के रास्ते में कांटा नहीं बन सकती. कांग्रस (आई) के

गुंडों की छटपटी कोशिशों के बावजूद, पश्चिम बंगाल में बंद संपूर्ण था.

समूचे देश में बैंकों, जीवन बीमा व आम बीमा में हड़ताल संपूर्ण थी. सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक तक भी कार्य नहीं कर सके, इनकी इमारतों के समक्ष भारी पुलिस बल का खाली कमरों ने मजाक उड़ाया. तेल कारखानों, कोयला, इस्पात, गोदी व बंदरगाह, इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल, दवा, लौह-खनिज, मैंगनीज, तांबा खदानों आदि में हड़ताल रही.

बंबई सुनसान थी. औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा व्यस्त वस्तु मंडियां जिनमें खाद्यान, रूई, धातु, बुलियन, रंग, रसायन, कपड़ा, जेवरात आदि की मंडियां शामिल हैं, बंद रहीं. पुणे में आकाशवाणी के समक्ष हड़ताल के बारे में झूठी खबरें प्रसारित करने के खिलाफ भारी प्रदर्शन आयोजित किया गया.

तमिलनाडु से प्राप्त समाचारों से पता लगता है कि मद्रास व सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्ण हड़ताल रही. कोयंबतूर में बंद सफल रहा. समूचे राज्य में परिवहन पर असर पड़ा.

इसी प्रकार के समाचार हरियाणा व पंजाब से प्राप्त हुए हैं. हरियाणा कंकास्ट व हांसी स्पिनिंग मिल्ज के क्रोधित मालिकान ने सभी दो हजार मजदूरों की सेवाएं खत्म कर दीं.

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, फैजाबाद, मुरादाबाद आदि औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल सफल होने के समाचार मिले हैं.

उड़ीसा व राजस्थान में भी यह बंद की तरह ही था. परिवहन तक स्थिर हो गया. उड़ीसा में हाईकोर्ट सहित सभी अदालतें बंद रहीं.

असम, मध्यप्रदेश व गुजरात के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल के समाचार दिए हैं.

दिल्ली में बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक ओखला क्षेत्र में हड़ताल संपूर्ण रही. पुलिस व इंटक के हड़ताल तोड़नेवालों द्वारा दबाव दिए जाने के बावजूद लारैंस रोड़, मायापुरी, वजीरपुर, नरैना आदि औद्योगिक क्षेत्रों में भारी तादात में मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. बताया जाता है कि ओखला क्षेत्र में दो दवा यूनिटों ने अपने दरवाजे खुद ही बंद कर दिए.

आंध्र प्रदेश में लगभग तीन हजार गिरफ्तारियों के बावजूद हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापतनम व अन्य स्थानों से पूर्ण बंद के समाचार मिले हैं. समाचार पत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री व भूतपूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री टी. अंजैया ने अपने प्रेस सम्मेलन से एक संवाददाता को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने हड़ताल को अच्छा समर्थन मिलने की खबर को "अनुचित" रूप से प्रकाशित की. गुस्से में लालपीला होकर उन्होंने कहा कि वह इस "गलती करनेवाले" पत्रकार को जेल भिजवा देंगे.

कर्नाटक में लाठीचार्ज व सैकड़ों गिरफ्तारियों के बावजूद मैसूर, बगलौर, देवंगिरि, बेलगाम व अन्य स्थानों पर हड़ताल सफल रही.

हड़ताल का महत्वपूर्ण गुण यह भी था कि समूचे देश में समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया. नैशनल हेरल्ड (जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित) जैसे कुछेक को छोड़कर देश में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ. इसी प्रकार की भागीदारी विश्वविद्यालय व स्कूल के अध्यापकों की थी. ज्यादातर राज्यों में सभी शिक्षा संस्थान बंद रहे. सभी राज्यों में राज्य सरकार कर्मचारियों ने अपने पहले फैसले के अनुसार भारी तादात में मुख्य धारा में भाग लिया. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों व अन्यों ने अपनी एकजुटता व्यक्त की. दिल्ली में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने अपने दोपहर के खाने के समय में बोट क्लब पर भारी रैली आयोजित की.

कुल मिलाकर समूचे देश में हड़ताल ने सभी पर भारी असर डाला. राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा बुलाए गए प्रैस सम्मेलन में संवाददाता भारी संख्या में आए. विभन्न देशों के संवाददाताओं ने सीटू कार्यालय से हड़ताल के बारे में बार-बार पूछताछ की.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने एक प्रैस बयान में मजदूर वर्ग को बधाई देते हुए मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों का आह्वान किया कि वे हड़ताल के माध्यम से प्राप्त एकता को और मजबूत करें ताकि सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने तक और अधिक दृढ़ निश्चयी संघष छेड़े जा सकें.

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति ने एक बयान जारी किया जिसमें मजदूर वर्ग का आह्वान किया गया कि वह वैकल्पिक आर्थिक नीति के लिए संघर्ष को आगे बढाए.

[आगामी अंक में और अधिक समाचार प्रकाशित किए जाएंग.]

सफल हड़ताल के लिए मजदूरों को सीटू द्वारा बधाई

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., ने 19 जनवरी को यह बयान जारी किया है:

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान का भारी समर्थन करने के लिए और आज की एक दिवसीय अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीटू देश के लाखों मजदूरों को बधाई देती है. विभिन्न कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में हमारे 50 हजार मजदूरों को गिरफ्तारी, जिसमें अनेक एन एस ए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस लाठी चार्ज, गोलीबारी और कांग्रेस(आई)के गुंडों द्वारा हमलों, जिनमें कई मजदूर मारे गए, द्वारा बर्बर दमन का बहादुरी से सामना करते हुए लाखों मजदूर हड़ताल में शामिल हुए और इस प्रकार देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में एक स्मरणीय अंक जोड़ा. पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व दिल्ली की ही खबरें यह बताती हैं कि मजदूरों ने इस आह्वान को शक्तिशाली समर्थन दिया है.

सीटू श्रीमती गांधी द्वारा किए गए बर्बर हमलों की निंदा करती है जिसने 50 हजार से ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार

[शेष पृष्ठ बारह पर]

कर्मचारियों को विभाजित करने का इरादा

भूतपूर्व वित्तमंत्री वेंकटरमन की घोषणा के अनुसार सरकार ने इरा सेझियान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जीवन बीमा निगम को पांच स्वाधीन यूनिटों में विभाजित करने का फैसला ले लिया है. उनके कथनानुसार इस विभाजन के लक्ष्य हैं जीवन बीमा को ग्रामीण इलाकों में ले जाना, उद्योग की प्रबंधन योग्य यूनिटों में पुनर्रचना, आपरेशनल क्षमता को बढ़ाना, खर्च कम करना, और कंपीटीशन की इजाजत देना और अधिक गति प्रदान करना. आगामी अधिवेशन में इस संबंध में विधेयक पेश किया जा सकता है.

ऐसे ऊंचे-ऊंचे इरादों को पेश करते हुए लाखों पोलिसी-होल्डरों की सुविधाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हैं.

आओ हम वित्तमंत्री द्वारा बताए गए इरादों का क्रांतिक तौर पर विश्लेषण करें.

ग्रामीण विकास : इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में विभाजन कैसे सहायता करेगा. असलियत में, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा के विकास को क्षति इसलिए पहुंची है क्योंकि सरकार की ही ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त शक्तियों व कार्यों सहित शाखाएं न खोलने की नीति है. वास्तव में, कई मौजूदा शाखाएं बंद कर दी गई हैं और नई डिविजनें खोलने के प्रस्ताव वर्षों से पूरी तरह फाइलों में ही हैं. ग्रामीण इलाकों में व्यापार का विकास केवल तब ही हो सकता था अगर पर्याप्त शक्तियों व कार्यों सहित अधिक शाखाएं खोलने की बैंक प्रणाली का अनुसरण किया जाता. क्योंकि मौजूदा एकक ढांचे में अधिक विकसित क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़े इलाकों को राहत देते हैं, विभाजन इस प्रणाली को खत्म कर देगा और पिछड़े क्षेत्रों को क्षति पहुंचेगी जिसके परिणामस्वरूप व्यापार व आपरेशनल क्षमता के नजरिये से असमान कार्पोरेशन होंगे.

प्रबंधन योग्य यूनिटें व आपरेशनल क्षमता : 'प्रबंधन योग्य यूनिट' की बात एक ढकोसला है. इस द्वारा यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एकक ढांचे के कारण जीवन बीमा निगम बहुत बड़ा व अक्षम हो गया है. यह सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है. विशाल स्टेट बैंक आफ इंडिया जो एक सार्वजनिक वित्त यूनिट है अभी भी मजबूत होता जा रहा है और ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक नई शाखाएं खोल रहा है. इस समय इसकी 5,546 शाखाएं है और 1,48,000 कर्मचारी हैं जबकि जीवन बीमा निगम में केवल 800 शाखाएं है और 44,000 कर्मचारी हैं. जीवन बीमा निगम में कमियां इसके विशालकाय होने के कारण नहीं हैं बल्कि ये शक्तियों व कार्यों के विकेंद्रीकरण की कमी तथा सरकार द्वारा ही इसकी स्वायत्तता में कमी के कारण हैं. 25 साल के बाद भी शक्तियों व कार्यों का स्तर तय नहीं किया गया है. इन सालों में, ब्यूरोक्रेसी को विवाद, भ्रष्टाचार तथा अड़चनों द्वारा स्वयं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.

जहां तक आपरेशनल क्षमता व खर्चों का संबंध है वे निम्न आंकड़ों में व्यक्त किए गए हैं:—

	दिसंबर 1957	मार्च 1980
मौजूदा पोलिसियों की क्षमता	54.17 लाख	220.39 लाख
इन्वेस्टिबल लाइफ फंड	410.41 करोड़	5818.90 करोड़
एल आई सी की कुल आय	112.90 करोड़	1297.78 करोड़
सालाना नया व्यापार	336.67 करोड़	2733.11 करोड़
कुल खर्च अनुपात	27.20 प्रतिशत	24.52 प्रतिशत
पुनर्नवीकरण खर्च अनुपात	15.89 प्रतिशत	13.01 प्रतिशत
वेतन व भत्ते	13 प्रतिशत	9 प्रतिशत

जीवन बीमा निगम में उपरोक्त भारी वृद्धि जहां आपरेशनल क्षमता का सबूत पेश करती है वहां यह व्यक्तिगत कर्मचारियों पर कार्यभार में वृद्धि को बेरोक प्रदर्शित करती है. जहां दिसंबर 1967 में एक अकेले कर्मचारी ने 276 पोलिसियों की सेवा की वहां उसने मार्च 1980 में 606 पालिसियों की देखभाल की. क्षमता में और आगे सुधार करने के लिए इस बात की जरूरत है कि विभिन्न कार्यालयों में स्टाफ की पर्याप्त भर्ती की जाय और प्रशासन की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में उनकी सक्रिय भागीदारी हो तथा उचित औद्योगिक संबंधों की गारंटी दी जाय.

जहां तक खर्चों में कमी करने का संबंध है सरकार इस इरादे के पीछे तर्क की व्याख्या नहीं कर सकती क्योंकि उपरोक्त आंकड़े खर्चों में कमी के सबूत हैं. विभाजन उद्योग में अधिक उच्चाधिकारी बनाएगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यर्थ खर्च होगा.

कंपीटीशन व गतिशीलता : वित्त मंत्री का कंपीटीशन का तर्क जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बुनियादी इरादे को धराशयी करता है क्योंकि यह निजी क्षेत्र में इस उद्योग में गला काटने वाले कंपीटीशन की बुराइयों को खत्म करने के लिए किया गया था. मौजूदा ढांचे में ही एक जोन का दूसरे जोन से, डिविजन का डिविजन से, और शाखा का शाखा से कंपीटीशन हो सकता है. इस लक्ष्य के विपरीत विभाजन से निजी क्षेत्र की भांति कंपीटीशन शुरू हो जाएगा और इससे गैरकानूनी कटौती व भ्रष्टाचार पैदा होंगे.

इसी प्रकार, जीवन बीमा निगम को विभाजित करके नहीं बल्कि अन्य बचत

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) केंद्रीय नियम, 46

[10 दिसंबर 1981 के एक नोटिफिकेशन द्वारा, भारत सरकार ने उपरोक्त नियमों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए, 45 दिन के समय में आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा. केंद्रीय कार्यालय ने इन संशोधनों को राय के लिए भेजा. केवल दो यूनियनों ने, दोनों आंध्र प्रदेश की, अपने सुझाव दिए. इन सुझावों पर विचार करने के बाद सीटू ने आपत्तियां उठाईं और निम्नलिखित कदम सुझाए.—संपादक]

सरकार ने कानून के शिड्यूल की मद-5 के क्लाज (ii) में संशोधन प्रस्तावित किया :

"छुट्टियों व होलीडेज की मात्रा, आवेदन के तरीके और शर्तें जिन पर आधारित होकर कंपीटेंट आथोरिटी ऐसी छुट्टियां या होलीडेज दे सकती है".

सीटू ने "शर्तें जिनपर आधारित होकर" शब्दों पर जो संशोधन में दिए गए हैं, आपत्ति उठाई है और सुझाव दिया है कि प्रस्तावित संशोधन को निम्नलिखित से बदल दिया जाए :

"छुट्टियों व होलीडेज की मात्रा, आवेदन के तरीके, कंपीटेंट आथोरिटी जो ऐसी छुट्टियां व होलीडेज दे सकती है, संस्थान में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श के बाद तय की जाएंगी और निष्कर्ष हर संस्थान के स्थायी आदेशों में साफ-साफ शामिल कर लिए जाएं".

सरकार ने शिड्यूल 1 (बी) के 1(i) में "सर्विस रिकार्ड" के शीर्षक के नीचे यह सुझाव दिया है :

"हर औद्योगिक संस्थान स्टैंडर्ड साइज में सर्विस रिकार्ड, जहां तक संभव हो सके, इन आदेशों के साथ इस लक्ष्य के लिए संलग्न फार्म में रखेगा, जिसमें हर कामगार का ब्यौरा रिकार्ड किया जाएगा और एक अफसर द्वारा, जो इसके लिए अधिकृत होगा, तिथि सहित सत्यापित किया जायगा".

सीटू ने सुझाव दिया कि इस नियम के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

"इस सर्विस रिकार्ड को सभी कामगारों द्वारा कम से कम छः महीनों में एक बार पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए और उस हालत में जब कोई कामगार सर्विस रिकार्ड को पढ़ने में पर्याप्त योग्य न हो तो ऐसे कामगार को अपनी पसंद के या तो एक ट्रेड यूनियन अधिकारी या उसी संस्थान में अपनी पसंद के दूसरे कामगार की मदद लेने की इजाजत दी जानी चाहिए, और यह काम करने के बारे में सर्विस रिकार्ड में अफसर, कामगार और मदद करने वाले कामगार के, यदि कोई है, हस्ताक्षर व तिथि सहित लिख दिया जाना चाहिए".

कामगार के रिहायशी पते के बारे में क्लाज (iii) के बाद निम्नलिखित जोड़ने का सीटू ने सुझाव दिया :

"उसके स्थायी आवास में परिवर्तन के बाद तीस दिन के समय के अंदर".

नियम 4 में "तबादला" शीर्षक के तहत "प्रशासनिक तथा फौरी ध्यान के काम" के नाम पर कामगारों के तबादले करने की शक्ति शामिल की जाने की कोशिश की गई.

सीटू ने इस क्लाज का विरोध किया और सुझाव दिया कि इसे खत्म कर दिया जाए क्योंकि मालिकान इसका इस्तेमाल ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को विक्टिमाइज करने के लिए कर सकते हैं.

इसी प्रकार "गोपनीयता" से संबंधित प्रस्तावित क्लाज 7 का भी सीटू ने विरोध किया क्योंकि इसका इस्तेमाल भी मालिकान कामगारों को विक्टिमाइज करने के लिए कर सकते हैं. सीटू ने सुझाव दिया कि इसे भी खत्म कर दिया जाए.

नियम 8 के तहत "एकमात्र सेवा" में सरकार ने प्रस्तावित किया :

"एक कामगार जिस औद्योगिक संस्थान में वह काम कर रहा है उसके हित के खिलाफ काम कभी नहीं करेगा और संस्थान में अपनी नौकरी के अलावा कोई और रोजगार नहीं लेगा जो मालिकान के हित को बुरी तरह से प्रभावित करेगा".

क्योंकि कानूनी ट्रेड यूनियन गतिविधि "संस्थान के हितों के खिलाफ" कही जा सकती है, इसलिए सीटू ने सुझाव दिया कि इस क्लाज में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिए जाएं :

"जिस औद्योगिक संस्थान में वह काम कर रहा है उसके हित के खिलाफ काम नहीं करेगा और".

फार्म v व माडल सर्विस रिकार्ड में "अनुशासनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा" शामिल किया जा रहा था. सीटू ने इसका विरोध किया और सुझाव दिया कि इसे खत्म कर दिया जाए.

सीटू के सुझाव मजबूत तर्कों पर आधारित हैं. सीटू ने संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाने से पहले सुनवाई के लिए भी कहा है.

लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूनियनों को अपने स्थायी आदेशों में इनमें से कोई भी हानिकारक क्लाज जोड़े जाने का विरोध करने के लिए सर्टीफाइंग आथोरिटी के समक्ष अवसर मिलेगा जिसे इस्तेमाल करना चाहिए. □

सीटू नामांकन

कोलंबो में 18 से 21 जनवरी को होनेवाली मजदूर शिक्षा पद्धति में परिशिक्षण पर आई एल ओ की कर्मशाला में भाग लेने के लिए सीटू ने जनरल काउंसिल के सदस्य डी. जानकीरमण को नामजद किया है.

वे 17 जनवरी को श्रीलंका के लिए रवाना हो गए. □

निरस्त्रीकरण के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

निरस्त्रीकरण के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर एक विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन 15 से 17 दिसंबर को पेरिस में संपन्न हुआ. 60 देशों व 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 206 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया.

सीटू की ओर से सीटू की पंजाब स्टेट कमेटी के अध्यक्ष जगजीतसिंह लायलपुरी ने सम्मेलन में भाग लिया.

रीगन प्रशासन द्वारा न्यूट्रान बम के उत्पादन की घोषणा से बढ़े न्यूक्लीयर युद्ध के खतरे और इस नीति के खिलाफ व शांति के लिए बढ़ते संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह सम्मेलन संपन्न हुआ.

प्रसाधनों की भारी बरबादी

एक अमरीकी, मेरियन एंडरसन, द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, हर बार अमरीका में मिलिटरी बजट में एक सौ करोड़ डालर की वृद्धि से 11,600 नौकरियां खत्म हो गयीं. अकेले 1970 से 1974 के दौरान अमरीका में मिलिटरी बजट की वृद्धि से 9,07,000 नौकरियां खत्म हो गयीं. स्वयं अमरीकी ब्यूरो आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स की परिकलनाओं के अनुसार पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक सौ करोड़ डालर के निवेश से कितनी नौकरियां निकल सकती थीं : शस्त्र : 75,710 नौकरियां, शिक्षा : 1,87,299; थोक व परचून व्यापार : 1,12,363; निर्माण : 1,00,072; यांत्रिक इंजीनियरिंग : 86,114; परिवहन : 92,071; सिविल सेवा : 86,977. उसी विश्लेषण से पता चलता है कि अगर 1980 के लिए अमरीकी सुरक्षा बजट में एक हजार करोड़ डालर की कटौती की गयी होती तो 2,45,000 नौकरियां पैदा करना संभव होता.

अमरीकी सुरक्षा बजट 1980 में 14,500 करोड़ डालर तक पहुंच गया, रीगन ने इसे बढ़ाकर 1982 के लिए 20,000 करोड़ डालर कर दिया और 1986 के लिए यह 40,000 करोड़ डालर होगा. इसका परिणाम हर कोई जान सकता है.

1980 के अंत में अमरीका में बेरोजगारी, वहां की ट्रेड यूनियनों के अनुसार, एक करोड़ थी. साम्राज्यवादी देशों में बेरोजगारी 2.4 करोड़ थी जिसमें से 30 लाख ब्रिटेन में थी.

बढ़ती मुद्रास्फीति

सम्मेलन ने यह सिद्ध किया कि मिलिटरी निवेश मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जो कीमत वृद्धि में प्रदर्शित होता है.

साम्राज्यवादी देशों में शस्त्रीकरण दौड़ ने 1980 में मुद्रास्फीति इस प्रकार बढ़ाई : यू. के. : 22 प्रतिशत; इटली : 20.5 प्रतिशत; टर्की : 21.5 प्रतिशत; पुर्तगाल : 15.2 प्रतिशत; स्पेन : 15 प्रतिशत; फ्रांस : 13.7 प्रतिशत; ग्रीस : 13.8 प्रतिशत. अमरीका में अगस्त 1978 व अगस्त 1980 के बीच मुद्रास्फीति 26 प्रतिशत हो गई.

सम्मेलन ने इस बात को नोट किया कि शस्त्र निर्माण की नीतियों के लिए कामकाजी जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि वित्तीय प्रसाधन भारी अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा जुटाए जाते हैं जिसका बोझ कामकाजी जनता व उसके परिवारों पर पड़ता है.

वास्तविक वेतन में कमी

इन देशों में मजदूरों के वास्तविक वेतन 1980 की तुलना में घटे हैं. अमरीका में 1973 व 1980 के दौरान मजदूरों के वास्तविक वेतन में 10.5 प्रतिशत गिरावट आई है.

विश्व में जहां 5 करोड़ व्यक्ति हर साल भूख से मरते हों, हर छः में से एक अल्पाहार का शिकार हो, पांच में एक अनपढ़ हो, तीन में से एक की सर्वाधिक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तक पहुंच न हो और करोड़ों बेरोजगार हों वहां धन का व्यापक व अभूतपूर्व दुरुपयोग किया जा रहा है. दूसरी ओर, शस्त्र निर्माण भारी मुनाफे (सिविल उत्पादन से 2 या 3 गुना ज्यादा) का बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए स्रोत है जो अपनी आर्थिक प्रभुता थोपते हैं और अपने मिलिटरी उत्पादन के विकास के लिए जनता के धन का प्रयोग करते हैं. अमरीका 500 सबसे बड़े एकाधिकारियों के मुनाफे 1979 तक 23 प्रतिशत बढ़ गए जबकि अमरीका में 1980 में सामाजिक कार्यक्रमों में 1,300 करोड़ डालर की कटौती की गई.

साम्राज्यवादी युद्ध साजिशें

मेहनतकश जनता को इस तरह बिगड़ते हालात में अमरीका साम्राज्यवादी देशों द्वारा युद्ध की तैयारियों में नेतृत्व कर रहा है और सोवियत संघ व समाजवादी देशों को सभी संभव दिशाओं से घेरने की कोशिशें कर रहा है. इसने लगभग 120 देशों में 2,500 मिलिटरी बेस स्थापित कर लिए हैं जो न्यूक्लीयर हथियारों से लैस हैं और इनका प्रबंध लगभग 5 लाख व्यक्ति कर रहे हैं. सोवियत संघ के निरस्त्रीकरण के बार बार आह्वान के बावजूद 1978 में नाटो ने अपने सम्मेलन में सदस्य देशों के मिलिटरी बजट में हर साल तीन प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला लिया. साल्ट-II संधि को स्वीकार करने से इंकार करते हुए पश्चिम जर्मनी में परशिंग व क्रुइज मिसाइल लगाने के अमरीकी फैसले ने सोवियत संघ को जर्मन भूमि से सीधे हमले के परास में ला दिया है.

एटमबम से 1945 में शुरू होकर, अमरीका बड़ी तेजी के साथ नए भरकम न्यूक्लीयर हथियारों की खोज व वृद्धि में लगा है. रीगन प्रशासन ने 6 अगस्त 1981 को न्यूट्रान बम का पूरे पैमाने पर उत्पादन करने का फैसला लिया. सोवियत यूनियन ने ऐसा नहीं किया हालांकि ऐसा करने की इसकी क्षमता है.

केवल सोवियत संघ को घेरने से संतुष्ट न होकर यह दक्षिण व दक्षिण

पश्चिम एशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में बढ़ते समाजवादी प्रभाव को रोका जा सके. पाकिस्तान के मिलिटरी शासक को इस द्वारा हथियारबंद किया जाना भारत को एक और युद्ध से धमकी दे रहा है.

अमरीका बेनकाब

जगजीत सिंह लायलपुरी ने अपने भाषण में यह बताया कि एकाधिकारी पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का इतिहास अहिंसा व युद्ध से भरा पड़ा है. 1954 से 25 वर्षों के थोड़े से काल में उन्होंने मानवता को दो विश्वयुद्धों में ढकेल दिया और मजदूर वर्ग की मेहनत से एकत्रित संपत्ति को लापरवाही के साथ नष्ट करने के साथ साथ चार करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया. उन्होंने कहा कि इन आक्रामक योजनाओं का स्रोत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो 1930 के बाद सबसे गहरे संकट में ग्रस्त है की छटपटाती हालत है. एकाधिकारी पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शस्त्रों का उत्पादन इस प्रकार अब जरूरत बन गया है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रभुत्ता के लिए अपनी तैयारियों में ग्रस्त अमरीका आज साम्राज्यवादी आक्रमण का सबसे बड़ा नेता है. उन्होंने जनता को भ्रम में डालने वाली अमरीका के 'दो बड़ी शक्तियों' के सिद्धांत की आलोचना की. जबकि वास्तव में सोवियत संघ अमरीकी धमकी के खिलाफ मिलिटरी सुरक्षा के लिए काफी धन लगाने के लिए बाध्य हुआ है. एशियाई, अफ्रीका व लैटिन अमरीकी देशों के प्रतिनिधियों ने युद्ध तैयारियों की अमरीकी नीति की तीखी आलोचना की और शांति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष में सोवियत संघ की भूमिका की प्रशंसा की.

सम्मेलन की घोषणा

सम्मेलन की अंतिम घोषणा ने प्रसाधनों के—मानवीय, वित्तीय व पदार्थिक, शस्त्रों का निर्माण करके, सामाजिक सुरक्षा के कदमों में कटौती करके और करोड़ों को बेरोजगारी व गरीबी में परिणत करके, भारी दुरूपयोग की ओर संकेत किया. इसने ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे युद्ध के लिए इन खतरनाक तैयारियों को खत्म कराने के लिए एकजुट संघर्ष की अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों के प्रति और विश्व के एक विशाल अस्त्रागार में, जो मानव जाति को समाप्त करने में अब काफी हैं, परिणत करने के प्रति सजग रहें.

बढ़ते संघर्ष

लेकिन अमरीका व साम्राज्यवादी देशों के इस रास्ते के खिलाफ शांति के संघर्ष को समूचे विश्व में समर्थन मिल रहा है. रीगनोमिक्स के खिलाफ स्वयं वाशिंगटन में ए एफ एल व सी आई ओ द्वारा एक प्रतिरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें 5 लाख लोगों ने भाग लिया. जनता द्वारा इसी प्रकार के भारी प्रदर्शन लंदन, बोन्न, पेरिस, ब्रसेल्स, हेल्सिकी, लिस्बन, रोम आदि सभी राजधानियों में आयोजित किए गए. आम नारे थे 'शांति लेकिन युद्ध नहीं' और 'न्यूट्रान बम मुर्दाबाद'.

मजदूर वर्ग की भूमिका

ऐसी घिनौनी हालत में जब अमरीका विश्व को न्यूक्लीयर नरसंहार की ओर घसीट रहा हो व स्वयं मानवजाति को नष्ट करने की धमकी दे रहा है, मजदूर वर्ग को चुनौती को स्वीकार करना चाहिए. कामकाजी जनता के पास जो विकल्प बचा है वह है जन संघर्ष. सभी देशों की क्रांतिकारी ताकतों को एकजुट होना है, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद करना है और समाजवादी खेमे की रक्षा करनी है. जीवन के हालात में सुधार के लिए और मेहनतकश जनता के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए विज्ञान व तकनीकी के विकास के लिए पूंजीवादी गठबंधन के खिलाफ तथा एकाधिकारी पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष को शांति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष के साथ जोड़ना होगा. □

गणतंत्र दिवस पर ए यू सी सी टी यू द्वारा सीटू को बधाई

ए यू सी. सी टी यू, मास्को, सोवियत संघ, से सीटू को यह संदेश प्राप्त हुआ है:

"प्रिय साथियों, संगठित सोवियत फैक्ट्री व आफिस मजदूरों तथा सामूहिक फार्म किसानों की ओर से आल यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियंज आपके देश की गणतंत्र की घोषणा की 32वीं वर्षगांठ के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय ट्रेड यूनियनों तथा कामकाजी जनता को हार्दिक बधाई देती है. हमारे देशों के बीच शांति, मित्रता व सहयोग की संधि होना, व उच्चस्तरीय सोवियत व भारतीय बैठकें सोवियत संघ व भारत की जनता के बीच बिरादराना संबंधों के धीरे धीरे विकास व मजबूत होने के सबूत हैं. सी पी एस यू की केंद्रीय समिति के महासचिव और सुप्रीम सोवियत के अध्यक्षमंडल के अध्यक्ष एल आई ब्रेझनेव की ऐतिहासिक यात्रा सोवियत संघ व भारत के बीच मित्रता व सहयोग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और न केवल एशिया बल्कि समूचे विश्व में शांति व प्रगति के समर्थन में एक महान महत्वपूर्ण कदम है. हम भारतीय कामकाजी जनता और उनकी ट्रेड यूनियनों के नए भारत के निर्माण में सफलताओं की कामना करते हैं.

आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियंज."

कामरेड मेजर जयपाल सिंह

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज 25 जनवरी 1982 को विजयवाड़ा में कामरेड मेजर जयपाल सिंह की अचानक मृत्यु पर गहरा दुख तथा अपना असांत्वनीय शोक प्रकट करती है. वे सी. पी. आई. (एम) की केंद्रीय समिति के सदस्य तथा इसकी दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव थे.

'मेजर साहब', जैसा कि उनके कामरेड प्यार से उनको पुकारते थे, मृत्यु के समय 65 वर्ष के थे. उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन युवावस्था में शुरू किया था जब वे तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अफसर थे. पनपते राष्ट्रीय आंदोलन के साथ होने तथा इसे महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के कारण 1946 में फोर्ट विलियम, कलकत्ता, में साम्राज्यवादियों ने उनका कोर्ट मार्शल किया. गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मुहम्मद अब्दुल कलाम आजाद व अन्य राष्ट्रीय कांग्रेस के बंदी नेताओं को खत्म करने की ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने साजिश की थी. वह सर्वाधिक गोपनीय दस्तावेज तत्कालीन संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया जिसने उसे पार्टी के अधिकृत मुखपत्र 'पीपल्स वार' में प्रकाशित किया. इस प्रकाशन तथा विश्व के समक्ष इस साजिश के इस तरह पर्दाफाश ने ब्रिटिश सरकार के हाथों को अपनी घिनौनी साजिश को पूरा करने से रोक दिया. अजेय किले, फोर्ट विलियम, से उन द्वारा बहादुरी के साथ बाहर निकल जाना अनुश्रुत है. वे फिर भूमिगत हो गए और निजाम से भूमि व स्वतंत्रता के लिए तेलंगाना के क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष में उन्होंने अगुवा भूमिका अदा की.

उनके भूमिगत जीवन को स्वतंत्रता से कोई छुटकारा नहीं मिला. ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट और मिलिटरी कोर्ट (कोर्ट मार्शल) के समक्ष क्रिमिनल मामले को कांग्रेस सरकार ने वापस नहीं लिया और इस महान क्रांतिकारी को कई सालों तक भूमिगत रहना पड़ा. अंततः पार्टी के पोलिट ब्यूरो के निर्देश पर उन्होंने कोर्ट के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया और वे कई सालों तक जमानत पर रहे. उन्हें हर पंद्रहवें दिन दिल्ली से कलकत्ता अपने केस में जिसे काफी लंबे समय तक समय समय पर स्थगित किया जा रहा था हाजिर होने के लिए जाना पड़ता था. अंत में कोर्ट ने केस को सबूत के न होने के कारण खारिज कर दिया. अनसुने कष्टों का सामना करते हुए कुल मिलाकर उन्हें 16 साल भूमिगत रहना पड़ा. उनको आठ साल जेल में बिताने पड़े जिसमें एमर्जेंसी का पूरा काल भी शामिल है.

लेकिन कष्ट और त्याग की कोई भी मात्रा उनके क्रांतिकारी कार्य व उत्साह में रूकावट पैदा नहीं कर सकी. आखिरी दम तक जब अचानक दिल का दौरा उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, कामरेड मेजर जयपाल सिंह ने अपना समूचा जीवन इस देश के मजदूर वर्ग और संघर्षरत जनता के हितों में लगाया. वे एक महान कम्युक्रांतिकारी का एक जीवंत उदाहरण थे. उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यू.पी., हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू व काश्मीर में सी पी आई (एम) और मजदूर वर्ग व किसान आंदोलन के निर्माण में प्रमुख व महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. विजयवाड़ा में सी पी आई (एम) की ग्यारहवीं पार्टी कांग्रेस की पूर्व संध्या को इसकी केंद्रीय समिति की बैठक में भाग लेते हुए कार्य में संलग्न कामरेड मेजर की दिल के भारी दौरे के बाद मृत्यु हो गयी.

उनकी याद में सी आई टी यू अपना झंडा झुकाती है. सी आई टी यू श्रीमती उषा जयपाल सिंह और शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों तथा सी आई टी यू व सी पी आई (एम) की दिल्ली राज्य कमेटियों को जिनके लिए यह क्षति पूर्तिहीन है अपनी हृदय विदारक संवेदना प्रेषित करती है. □

कामरेड ज्योर्तिमय बसु

प्रसिद्ध सांसद और लोक सभा में सी पी आइ (एम) के मुख्य सचेतक कामरेड ज्योर्तिमय बसु के 12 जनवरी को अचानक निधन पर सी आई टी यू अपना गहरा शोक व्यक्त करती है.

संसद में 15 सालों के दौरान उन्होंने मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा में लगातार संघर्ष किया. अधिनायकवाद के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्पी संघर्ष ने और इंदिरा निजाम के वास्तविक चेहरे को लगातार बेनकाब करने ने एमर्जेंसी के दौरान सरकार के रोष को आंमत्रित किया और उन्हें जेल में रखा गया व तंग किया गया.

शोक संतप्त परिवार को सी आई टी यू अपनी हृदयविदारक संवेदना भेजती है. □

इस्पात मजदूरों का सफल अखिल भारतीय सम्मेलन

दुर्गापुर में 8-10 जनवरी 1982 को संपन्न अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन ढाई लाख इस्पात मजदूरों की देशव्यापी एकता के निर्माण में एक दृढ़ कदम था. इंटीग्रेटिड इस्पात प्लांटों, कोल वाशरीज, कैप्टिव खदानों, सेंट्रल मार्किटिंग आर्गेनाइजेशन व ठेका मजदूरों के 520 प्रतिनिधियों तथा 81 प्रेक्षकों ने सम्मेलन में भाग लिया. इक्कीस कामगार महिलाओं ने प्रतिनिधि के रूप में तथा 3 ने प्रेक्षक के रूप में भाग लिया. सैकडों वालंटियरों ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिन रात काम किया.

सोवियत संघ व चीन के प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी सम्मेलन की खास बात थी. विदेशों के चौदह ट्रेड यूनियन संगठनों ने सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए बिरादराना संदेश भेजे.

पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष द्वारा ध्वजारोहण के साथ सम्मेलन शुरू हुआ. शहीद स्तंभ पर विभिन्न नेताओं व विदेशी प्रतिनिधियों ने फूल मालाएं चढ़ाईं. सम्मेलन के लिए निर्मित विशेष पांडाल का नाम दुर्गापुर स्टील के दो मजदूरों आशिष व जब्बर जिन्होंने 1966 में इस्पात मजदूरों के गौरवशाली संघर्ष में अपना जीवन बलिदान कर दिया था, के नाम पर रखा गया. सम्मेलन की कार्यवाही चलाने के लिए चंद्रशेखर मुखर्जी (बर्नपुर), अजीत मुखर्जी (दुर्गापुर), के के त्रिपाठी (जमशेदपुर), शिंगोरे (भिलाई) तथा निहिर जोरदार (सी एम ओ) सहित एक अध्यक्षमंडल चुना गया. दिवंगत नेताओं व शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी प्रतिनिधि दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए.

स्वागत समिति के अध्यक्ष रोबिन सेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए दुर्गापुर के मजदूरों की लड़ाकू परंपरा की समीक्षा की और इस्पात नगरी में ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण में पिछले दो दशकों में मजदूरों के त्याग को नोट किया.

अपने उद्घाटन भाषण में कृष्णपद घोष ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग व आम जनता पर बढते हमलों की ओर इशारा किया तथा बताया कि इस्पात मजदूर भी इन नीतियों के शिकार हुए. उन्होंने बताया कि आई एम एफ से हाल ही में लिए गए ऋण के क्या परिणाम होंगे और कहा कि वेतन जाम रूपी भारी हमला होने वाला है. इस हमले का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने इस्पात मजदूरों का आह्वान किया.

उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की श्रम नीतियों का हवाला दिया और बताया कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार, जो मजदूर वर्ग से टकराव की बात करती है, द्वारा अपनाई गई नीतियों से किस प्रकार बुनियादी तौर पर अलग हैं. कांग्रेस (आई) सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को शिकस्त देने के लिए मजदूरों की बढ़ती एकता का उन्होंने स्वागत किया.

उद्घाटन के बाद सीटू सचिव एम. के. पंधे ने सोवियत संघ व चीन के प्रतिनिधियों का परिचय कराया. उन्होंने कहा कि सोवियत संघ व चीनी प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर देखने का सौभाग्य मजदूरों को पहली बार प्राप्त हुआ है. 'हिंदी-चीनी भाई भाई', 'हिंदी-रूसी भाई भाई', 'रूसी-चीनी भाई भाई' के नारे लगाए गए.

इसके बाद ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान के अनुसार 19 जनवरी को एक दिन की आम हड़ताल करने के लिए इस्पात मजदूरों का आह्वान करते हुए एम. के. पंधे ने एक प्रस्ताव पेश किया. प्रत्येक इस्पात प्लांट से एक-एक प्रतिनिधि ने प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखे और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.

तैयारी समिति की ओर से जिबन राय ने सम्मेलन के समक्ष जनरल रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में विभिन्न केंद्रों में इस्पात मजदूरों के आंदोलन की वृद्धि और इस्पात मजदूर यूनियन की को-आर्डिनेशन कमेटी की संगठन के निर्माण तथा विभिन्न कक्षों में गतिविधियों के तालमेल में भूमिका की समीक्षा की गई. रिपोर्ट में इस्पात उद्योग की दशा की भी समीक्षा की गई तथा इस्पात मजदूरों के कार्य व जीवनयापन के हालात में सुधार करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया.

जनरल रिपोर्ट में इस्पात उद्योग में तीन समझौतों का उल्लेख किया गया तथा यह नोट किया गया कि दुर्गापुर यूनियन व सीटू ने उनमें किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इसमें अगले वेतन समझौतों में और भी ज्यादा मांगों की प्राप्ति के लिए जोरदार संघर्ष करने के लिए आह्वान किया गया.

रिपोर्ट ने उद्योग में कुप्रबंध तथा बढ़ते भ्रष्टाचार की आलोचना की और इशारा किया कि यह उद्योग के विकास में किस प्रकार बाधा डाल रहा है. इसने इस कथन का विरोध किया कि इस्पात मजदूर अधिक वेतन वाले तबके हैं और यह नोट किया गया कि किस प्रकार पिछले दिनों इस्पात मजदूरों की दशा बिगड़ी है. रिपोर्ट में इस्पात मजदूरों के अखिल भारतीय संगठन के निर्माण की जरूरत भी नोट की गई ताकि पूंजीवादी हमलों के खिलाफ इस्पात मजदूरों के संघर्ष को तेज किया जा सके.

सम्मेलन ने स्टील वर्कर्ज फेडरेशन आफ इंडिया की स्थापना पर एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें कहा गया कि यह "इस्पात मजदूरों के हाथों में उनके आने वाले संघर्षों में एक शक्तिशाली हथियार होगी." इसने सभी इस्पात मजदूरों का इस फेडरेशन के झंडे के नीचे लामबंद होने का आह्वान किया ताकि इस्पात मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट आंदोलन शुरू किया जा सके.

सोवियत संघ व चीन के बिरादराना प्रतिनिधियों के भाषणों के दौरान सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा बार बार तालियां बजी. वे भारतीय मजदूर वर्ग के साथ बिरादराना एकजुटता के संदेश लाए जिनसे प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिली. मटैलर्जीकल इंडस्ट्री वर्कर्स यूनियन आफ यू एस एस आर की सेंट्रल कमेटी से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसकी सचिव नीना नेदोसेकिना ने किया जबकि यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के बोरिस चाशिकिन प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे. चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस के सचिव मंडल के आल्टरनेट सदस्य हान रुजीया ने किया जबकि चाइनीज ट्रेड यूनियन आफ मटैलर्जीकल इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष गांग लिन तथा ए सी एफ टी यू के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के हुआंग हुइफेन इसके सदस्य थे.

हान रुजीया ने अपने भाषण में चीन व भारत के बीच ऐतिहासिक संबधों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जनता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास, अपने देशों के निर्माण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा विश्वशांति को बनाए रखने के कामन कामों में जुटी हैं."

रुजीया ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि "भारतीय मजदूरों के खास तौर से भारतीय लौह व इस्पात मजदूरों के कार्य, जीवन व अन्य पहलुओं को स्वयं देखने के लिए मिले इस अवसर से हम बहुत ही प्रसन्न हैं. हम चीनी मजदूर वर्ग को यह बताएंगे कि हमने यहां क्या देखा व अपनी यात्रा के दौरान हमने क्या अनुभव प्राप्त किया तथा हम उन्हें चीन व भारत के बीच दोस्ताना संबंधों के आगे विकास में सहायता के लिए और हमारे दोनों देशों के मजदूर वर्ग के बीच मित्रता को मजबूत करते रहने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियनों की दोस्ताना भावना का संदेश देंगे. चीनी प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन को एक सुंदर पेंटिंग भेंट दी.

नीना नेदोसेकिना ने अपने भाषण में सोवियत संघ व भारत के बीच जीवन के हर पहलू पर बढ़ती दोस्ती पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा "हमारी यूनियन की सेंट्रल कमेटी व इसके सभी सदस्य भारतीय इस्पात मजदूरों के साथ हमारे अच्छे संबंधों से खुश हैं और उन्हें गर्व है. यूनियनों के उच्च स्तर पर बैठकें व सलाह मशविरे नियमित रूप से देखे जा रहे हैं." विश्वशांति की सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी एकजुट संघर्ष की जरूरत की ओर उन्होंने इशारा किया.

नीना ने कहा कि "आप इस्पात मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष में महान् सफलताओं के लिए हमारी सर्वोत्तम शुभकामनाएं स्वीकार करें. हमारे दोनों देशों के इस्पात मजदूरों के बीच दोस्ताना संबंध हर साल बढ़ें."

अपने भाषण का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि आप उन सब तक जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं यह पहुंचा दीजिए कि "विश्व में शांति व सामाजिक प्रगति के निमित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात मजदूरों व

बाएं : नीना नेदोसेकिना, मटैलर्जीकल वर्कर्स यूनियन, सोवियत संघ, की केंद्रीय कमेटी की सचिव, सम्मेलन का अभिनंदन करती हुई. साथ में है दूसरे प्रतिनिधि उसी यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के बोरिस चाशिकिन. बीच : चीनी प्रतिनिधिमंडल भेंट देते हुए. दाएं : रूसी व चीनी प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग लेते हुए.

उनकी यूनियनों में एकता व तालमेल स्थापित करने के पथ पर एक और कदम रखने के इस सम्मेलन के फैसले में हमारा दृढ़ विश्वास है. सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन को एक उपहार भेंट किया जिसे इस्पात मजदूरों ने सवियत संघ व भारत के इस्पात मजदूरों के बीच एकजुटता को दर्शाते हुए बनाया था.

सम्मेलन की ओर से बंगाली हथकरघे के उपहार बिरादराना संगठनों व प्रतिनिधियों को दिए गए. इस अवसर पर सम्मेलन में भावभीना वातावरण था. जब सोवियत प्रतिनिधिमंडल को एक सोवेनियर भेंट किया उस समय उनका जोशिले नारों से स्वागत हुआ.

टी यू आइ आफ मेटल इंडस्ट्रीज (डब्लू एफ टी यू), आई एल ओ, जेनेवा तथा रोमानिया, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, ईराक, कुवैत, बंगलादेश, साइप्रस व आस्ट्रेलिया जैसे बिरादराना संगठनों से प्राप्त संदेशों को बामापद मुखर्जी ने पढ़कर सुनाया.

रिपोर्ट पर बहस के दौरान प्रतिनिधियों ने इस्पात उद्योगों में बढ़ते आंदोलन और संयुक्त आंदोलन के निर्माण में अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया. कई ठेका मजदूरों ने अपनी दुखमय स्थिति के बारे में बताया और एकजुटता संघर्षों के लिए सभी इस्पात मजदूरों से अपील की. उन्होंने रिपोर्ट में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए और उसकी कमियों को नोट किया. रिपोर्ट पर बहस में महिला प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. मनोरंजन राय, एम. के. पंधे, मुहम्मद अमीन तथा लक्ष्मी सेन ने सम्मेलन को संबोधित किया.

सम्मेलन ने नवनिर्वाचित वर्किंग कमेटी को सम्मेलन में हुई बहस के आधार पर जनरल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया. संविधान के मसविदे के संबंध में भी इसे अंतिम रूप देने के लिए सम्मेलन ने वर्किंग कमेटी को अधिकार दिया. सम्मेलन ने फैसला लिया कि फेडरेशन का झंडा लाल रंग का होगा और इस पर सफेद रंग में हसिया-हथौड़ा तथा एस डब्लू एफ आई लिखा होगा.

सम्मेलन ने बिना मुआवजे के टिस्को के राष्ट्रीयकरण पर, जमशेदपुर व अन्य मजदूरों के विक्टिमाइजेशन के खात्मे पर, राउरकेला स्टील प्लांट के तहत बरसुआ खदान में हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता पर, गुप्त मतदान द्वारा इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति को मान्यता पर, एस्मा पर, आई एम एफ ऋण पर, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से हलदिया कंप्लैक्स को हटा लेने के खिलाफ और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ साजिशों पर प्रस्ताव अपनाए. एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने साम्राज्यवादी साजिशों व बढ़ते खतरे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह इस खतरे के खिलाफ और हिंद महासागर व विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करें.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद करते हुए दो महान समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया. उन्होंने सोवियत संघ से मिली सहायता का स्वागत किया और चीन के साथ दोस्ताना संबंधों के विकास की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने श्रीमती गांधी की अधिनायकवादी नीतियों की कड़ी निंदा की और इस्पात मजदूरों का इनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आह्वान किया. उन्होंने इस्पात मजदूरों को उनके संघर्ष में पूरा समर्थन देने का पूरा आश्वासन दिया.

एस के एन चौधरी ने क्रेडेंश्यल कमेटी की रिपोर्ट पेश की. एम. के. पंधे ने स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की 45 सदस्यीय वर्किंग कमेटी के नाम पेश किए जिनका समर्थन टी. एन. सिंह ने किया. सम्मेलन ने निम्न पदाधिकारी चुने: अध्यक्ष: समर मुखर्जी; कार्यकारी अध्यक्ष: दिलीप मजूमदार; उपाध्यक्ष: एम. के. पंधे, अजीत मुखर्जी, के. के. त्रिपाठी, पी. के. मुखर्जी, चंद्रशेखर मुखर्जी; महासचिव: जिबन राय; संयुक्त महासचिव: अर्धेंधु दक्षी; सचिव : नंदजी पंधे, यादव प्रसाद, तपन सेन, डी. भट्टाचार्य (एक स्थान राउरकेला से बाद में भरा जाएगा); कोषाध्यक्ष : मृनाल बनर्जी.

अपने समापन भाषण में समर मुखर्जी ने इस्पात मजदूरों का आह्वान किया कि वे फेडरेशन को मजबूत बनाएं ताकि संयुक्त संघर्ष का निर्माण समूचे देश में हो सके.

प्रतिनिधियों में बहुत ही उत्साह के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ और उन्होंने मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के नारे लगाए.

सम्मेलन के दौरान मानव समाज के विकास पर एक रंगीन प्रदर्शनी आयोजित की गई. रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों मजदूरों ने भाग लिया. इस अवसर पर एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गयी जिसमें इस्पात उद्योग के बारे में सूचनाएं विस्तार से दी गई थीं.

सैंकड़ों जुलूस लाल मैदान पहुंच कर एक विशाल रैली में परिवर्तित हो गए जिसकी अध्यक्षता दिलीप मजूमदार ने की. सोवियत संघ व चीन के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के फैसलों का स्वागत किया और भारतीय इस्पात मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की. रैली को ज्योतिबसु, समर मुखर्जी, एम. के. पंधे व जिबन राय ने अन्यों के अलावा संबोधित किया. □

सीटू की मासिक पत्रिकाएं

सीटू मजदूर

व

दि वर्किंग क्लास

(अंग्रेजी में)

एक प्रति की कीमत : 50 पैसे

सालाना चंदा : 6 रुपये

कम से कम 5 प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

जीवन बीमा निगम का विभाजन.....

[पृष्ठ तीन से आगे]

संस्थान के साथ कारगर कंपीटीशन के लिए उचित आधार बनाकर ज्यादा गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है. समुदाय के विभिन्न हिस्सों की जरूरत पूरा करने के लिए बीमा योजनाओं के उपयुक्त निर्माण द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना करके, पोलिसीहोल्डरों के लिए आकर्षक लाभ व बोनस का प्रावधान करके और किस्त दर घटा कर ऐसा किया जा सकता है.

बढ़ते अधिनायकवाद व बढ़ते संघर्षों की मौजूदा स्थिति में जीवन बीमा निगम को विभाजित करने का सरकार द्वारा व्यक्त किया गया लक्ष्य साफ साफ यह जाहिर करता है कि सरकार का मुख्य इरादा कर्मचारियों को विभाजित करने का है. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के जनवादी अधिकारों तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष सरकार को भाए नहीं. इसलिए लाखों पोलिसीहोल्डरों के हितों के प्रति अंधी होती हुई यह अपना गुस्सा जीवन बीमा कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों पर निकालेगी.

आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन तथा अन्य संगठन विभाजन के पूरी तरह खिलाफ हैं. संघर्ष कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं. जीवन बीमा कर्मचारियों पर यह हमला जीवन बीमा निगम से बाहर भी लाजिमी तौर पर होगा. जीवन बीमा निगम (संशोधन) कानून को बरकरार रखने काले सुप्रीम कोर्ट के पतनोन्मुख फैसले ने सरकार को विभाजन प्रस्ताव के प्रति प्रोत्साहन दिया हैं. मजदूर वर्ग व कामकाजी जनता के सभी हिस्सों को जीवन बीमा निगम के मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए एकजुट संघर्ष करने चाहिएं.

जीवन बीमा निगम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामूहिक सौदेबाजी पर चोट

सीटू सचिव एम के पंधे ने 2 जनवरी को यह बयान जारी किया:

जीवन बीमा निगम (संशोधन) कानून के औचित्य को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तथा बोनस व महंगाई भत्ते के संबध में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियो की मौजूदा सेवाशर्तों में एकतरफा परिवर्तन वाले मंत्रालय के 2 फरवरी 1981 के नोटिफिकेशन से सभी ट्रेड यूनियनों के लिए कई गंभीर व फौरी सवाल पैदा हुए हैं. वास्तव में, फैसले के नतीजे जीवन बीमा निगम के बाहर भी असर करेंगे.

साधारण भाषा में फैसले का अर्थ है कि सरकार आदेशों द्वारा सेवाशर्तें निर्धारित करने के लिए और औद्योगिक विवाद कानून द्वारा जो थोड़ी-बहुत सुरक्षा प्रदान की गई है उससे कर्मचारियों को बाहर रखने के लिए द्विपक्षीय समझौते के किसी भी प्रावधान को किसी भी दिशा में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त कर सकती है. इस तरह के प्रबंध का अर्थ है सामूहिक सौदेबाजी का पूरी तरह खात्मा हो जाना.

रोजाना गहराते आर्थिक संकट के संबंध में यह फैसला सरकार की, जो वेतन जाम व वेतन कटौती की नीति लागू करने में लगी है, मदद करेगा. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ अपने संबंध मेहनतकश जनता पर कुठाराघात करके सुधारने की कोशिश कर रही है.

सीटू सरकार से अनुरोध करती है कि 1974 के समझौते के प्रावधानों को बेरोक जारी रखे और कर्मचारियों के मांगपत्र पर सामूहिक सौदेबाजी द्वारा समझौता करे.

सीटू ट्रेड यूनियनों से न्यायिक फैसलों में नवीनतम रूझान को नोट करने, कटु संघर्षों द्वारा अर्जित अधिकारों व सुविधाओं में ऐसी घुसपैठ के खिलाफ मजदूरों को लामबंद करने तथा प्रतिरोध की आवाज बुलंद करने की अपील करती है. ट्रेड यूनियनों की केवल एकजुट आवाज ही इस प्रक्रिया को रोक सकती है. □

मध्य प्रदेश को कोयला खदानों में प्रबंधकों के गुंडों द्वारा आतंक

चुर्चा व बिश्रामपुर कोयला खदानों के प्रबंधकों की शह पर समाजविरोधी तत्वों ने पुलिस की मदद से मजदूरों के छटनी के खिलाफ संघर्ष को दबाने के लिए आतंक पैदा करना शुरू कर दिया है.

मजदूरों व उनके परिवारों द्वारा 1 दिसंबर को चुर्चा कोयला खदान पर भारी प्रदर्शन के बाद प्रबंधकों के गुंडे व पुलिस रात को मजदूरों पर टूट पड़ी और अधाधुंध पिटाई शुरू कर दी. यहां तक कि एक गभवती को भी नहीं छोड़ा गया तथा उसका गर्भपात हो गया. दृढ़ निश्चयी मजदूरों ने संघर्ष जारी रखा और काम बंद कर दिया. प्रबंधकों ने पुलिस-गुंडा गठबंधन द्वारा बिश्रामपुर में एक नया मोर्चा खोल दिया. दूसरे दिन सीटू यूनियन के दो पदाधिकारियों पर गुंडों ने हमला कर दिया. छः दिसंबर को ए एल सी के दफ्तर में संपन्न एक त्रिपक्षीय बैठक से प्रबंधको व स्वयं सरकार के अड़ियल रवैये के कारण विवाद का कोई समाधान नही हो सका. उसी रात कोयला श्रमिक संघ (सीटू) के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया. मजदूरों द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर हथियारबंद पुलिस व प्रबंधकों के गुंडों ने मजदूरों पर एक बार फिर हमला बोल दिया. मजदूरों पर लाठियां, अग्नि गोले व अश्रुगैस खुले तौर पर फेंके गए. 14 महिलाओं सहित 74 मजदूरों को जिनमें बच्चे भी शामिल हैं गिरफ्तार किया गया. 30 मजदूरों पर धारा 307 आई पी सी लगाई गई.

[शेष पृष्ठ बारह पर]

19 जनवरी : एक स्मरणीय दिवस

[पृष्ठ दो से आगे]

करके और पुलिस व पैरामिलिट्री बल के संरक्षण में गुंडों को, जिन्होंने कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता होने का छल किया, हड़ताली मजदूरों पर खुल्लमखुल्ला हमले करने के लिए प्रोत्साहित करके इस शक्तिशाली कार्यवाही को धराशयी करने की कोशिश की.

इतिहास में 19 जनवरी एक स्मरणीय दिवस होगा जब मजदूर वर्ग ने देश की समूची जनता के लिए आवाज बुलंद की. सीटू मजदूर वर्ग से श्रीमती गांधी के अधिनायकवादी निजाम की बडे भूपतिपरस्त, जन विरोधी, मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को बदलने के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए इस एकता को भविष्य में बनाए रखने व और मजबूत करने के लिए अपील करती है.

सीटू उन बहादुर मजदूरों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने संघर्ष को सफल बनाने के लिए तैयारियों के दौरान कांग्रेस के गुंडों के हाथों या पुलिस गोलीबारी में अपनी जानें कुरबान की और उनके शोक, संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदना भेजती है. □

मध्य प्रदेश कोयला खदान

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

इससे संतुष्ट न होकर, प्रबंधकों ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से मदद लेकर कोट कोना व भाटगोवा के ग्रमीणों के खिलाफ उन्हें उखाड़ फेंकने की लड़ाई शुरू कर दी है. खदानों के निर्माण के बाद ग्रमीणों को बिना कोई मुआवजे दिए या कोई नौकरी दिए उखाड़ दिया गया है. अविचलित मजदूरों ने प्रबंधक-गुंडा-पुलिस गठबंधन के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर दिया है. कोयला श्रमिक संघ (सीटू) ने 11 जनवरी को एक भारी प्रदर्शन आयोजित किया जिसमें 2 हजार मजदूरों ने भाग लिया.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र में आल इंडिया कोयला मजदूर फेडरेशन ने मध्य प्रदेश कोयला खदानों में प्रबंधकों के गुंडों की गुंडागर्दी, जिसमें राज्य मशीनरी भी शामिल है, बेशर्त खत्म करने की मांग की. सभी गिरफ्तार किए गए मजदूरों को बिना शर्त रिहा करने तथा झूठे मामले वापस लेने की भी फेडरेशन ने मांग की है. इसने पुलिस अत्याचार के शिकारों के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की है. □

राष्ट्रीय अभियान समिति आई एल ओ के डायरेक्टर जनरल से मिलेगी

राष्ट्रीय अभियान समिति नई दिल्ली में 27 जनवरी को आई एल ओ के डायरेक्टर जनरल से भारत सरकार द्वारा संगठन की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में विचार करने के लिए मिलेगी. सीटू का प्रतिनिधित्व महासचिव पी. राममूर्ति करेंगे. □

सीटू प्रकाशन

बढ़ता दमन, शक्तिशाली संघर्ष

(हिंदी में)

लेखक :

बी. टी. रणदिवे

अध्यक्ष, सीटू

कीमत : 80 पैसे

लिखें :

सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	सितं.	अक्टू.	नव.
बिहार			
जमशेदपुर	429	435	435
झारिया	425	433	442
कोडर्मा	476	478	497
मोंघाइर	498	503	513
नोआमुंडी	437	432	426
गुजरात			
अहमदाबाद	444	446	447
भाव नगर	460	458	462
हरियाणा			
यमुना नगर	480	488	493
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	482	492	497
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	477	479	478
भोपाल	479	481	483
ग्वालियर	483	483	481
इंदौर	484	484	488
महाराष्ट्र			
बंबई	458	466	470
नागपुर	481	488	484
शोलापुर	499	501	508
पंजाब			
अमृतसर	474	479	485
राजस्थान			
अजमेर	492	478	478
जयपुर	499	495	491
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	442	454	449
सहारनपुर	458	472	471
वाराणसी	496	498	505
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	444	464	464
कलकत्ता	408	429	426
दार्जीलिंग	360	376	379
हावड़ा	392	411	407
जलपाइगुरी	357	369	362
रानीगंज	425	442	441
दिल्ली	480	481	480
भारत	447	460	462

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ई. सी. एल को समझौता करने के लिए मजबूर किया

सीटू, एटक, यू टी यू सी, एच एम एस, बी एम एस और इंटक (दारा) द्वारा हड़ताल के संयुक्त नोटिस ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधकों को यूनियनों के साथ एक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया.

प्रबंधकों द्वारा पिछले कई वादों को पूरा न किए जाने के कारण यूनियनों द्वारा संयुक्त संघर्ष शुरू किया गया था. अंततः 4 जनवरी को हड़ताल के एक संयुक्त नोटिस ने प्रबंधकों को 30 दिसंबर से वार्ता शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया. सीटू की ओर से एम. के. पंधे व बामापद मुखर्जी ने बातचीत में हिस्सा लिया. सीटू प्रतिनिधियों ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधकों की उनके अड़ियल व श्रम विरोधी रवैये के कारण, जो हड़ताल के फैसले के लिए जिम्मेदार था, निंदा की. उन्होंने प्रबंधकों की जे बी सी सी आई को ठीक से चलाने में नाकामयाब होने का भी संकेत किया. इसके कारण मजदूरों में काफी रोष है.

चार दिनों तक चली लंबी बातचीत के बाद 2 जनवरी को सी आई एल के अध्यक्ष ने, जिसने बैठक में भाग लिया था, अंततः समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके परिणामस्वरूप हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया.

समझौते के अनुसार विक्टिमाइज किए गए सभी कर्मचारियों को एक जनवरी से पुनः बहाल कर लिया गया. अन्य सुविधाएं, जो एकतरफा वापस ले ली गयी थीं, भी बहाल की जाएंगी. प्रबंधकों ने एल टी सी, ग्रेच्युटी व लाइफ कवर योजना के बकाया भी देना स्वीकार कर लिया. तबादलों के सवाल पर कर्मचारियों को तंग करना खत्म करना भी प्रबंधकों ने स्वीकार किया. उन्होंने सतग्राम, श्रीपुर आदि के तबादले के मामलों पर यूनियनों के साथ फैसला करना भी स्वीकार किया. यह भी तय किया गया कि घायल मजदूरों को दिए गए मुआवजों में भी जे बी सी सी आई में अंतिम फैसला होने तक कोई कटौती नहीं की जाएगी. यह तय हुआ कि अन्य मांगों पर यूनियनों के साथ मार्च के अंत तक बातचीत होगी. □

लाइमस्टोन व डोलोमाइट लेबर वेल्फेयर फंड के सेंट्रल एड्वाइजरी बोर्ड की बैठक

भारत सरकार के श्रम विभाग ने लाइमस्टोन व डोलोमाइट लेबर वेल्फेयर बोर्ड के सेंट्रल एड्वाइजरी बोर्ड की बैठक 8 साल के अंतराल के बाद 2 जनवरी को बुलाई. सीटू प्रतिनिधि अजेय राउत ने और मजदूरों के अन्य प्रतिनिधियों ने सभी कार्यों के लिए बोर्ड को निष्क्रिय बनाने के लिए सरकार की आलोचना की. उन्होंने सरकार की इसलिए भी आलोचना की कि बैठक की कार्यसूची उन्हें नहीं दी गई थी. लेकिन सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उपयुक्त कार्यसूची के साथ बोर्ड की बैठक साल में दो बार बुलाई जाया करेगी.

लाइमस्टोन व डोलोमाइट मजदूरों के कल्याण के लिए सीटू ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

कम्युनिटी केंद्रों के लिए अनुदान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाए, लौह खनिज व मैंगनीज की भांति टाइप-II मकानों की योजनाएं, स्कूली बच्चों के लिए बसें, लौह खनिज व मैंगनीज की तरह दोपहर का खाना, रिहायशी टी. बी. रोगियों के लिए 50 रूपये, बनावटी अंगों की सप्लाई पर पूरा खर्च, पुस्तकालय की किताबों के लिए अनुदान, आदि. सरकार के प्रतिनिधि ने सुझावों पर विचार करना स्वीकार किया.

प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे मजदूरों पर अनुपातिक किराया थोपकर मकानों के निर्माण में निवेश की पूंजी वापस लेना चाहते हैं. लेकिन यह मजदूरों और यहां तक कि सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अस्वीकार कर दिया.

स्वचालन के खिलाफ

समाचारपत्र कर्मचारियों का अखिल भारतीय आंदोलन

समाचार उद्योग में स्वचालन के खिलाफ समूचे देश में आंदोलन करने के लिए समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों ने अपने संगठनों को मजबूत कर लिया है.

मालिकान व स्वयं सरकार ने उद्योग में फोटो-टाइप सैटिंग तकनीकी लागू करने की नीति अपना ली है जो हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार बना देगी (जनवरी अंक में प्रकाशित). इस बारे में सरकार ने पहले ही कई लाइसेंस दे दिए हैं.

नैशनल कनफेडरेशन आफ न्यूजपेपर व न्यूज एजेंसी एंप्लाईज आर्गेनाइजेशन ने समूचे देश में फरवरी से आंदोलन शुरू करने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया है. कार्यक्रम में स्वचालन के खतरों के बारे में पर्चे बांटने, बिल्ले लगाने, गेट मीटिंगें करने और 10 फरवरी को प्रदर्शन करने, 25 फरवरी तक स्वचालन विरोधी राज्यानुसार सम्मेलन पूरे करने, 17 मार्च को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करने और 18 मार्च को संसद पर एक मोर्चा आयोजित करने की कार्यवाहियां शामिल हैं.

याद रहे कि समाचार पत्र व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों ने 19 जनवरी को समूचे देश में पूर्ण हड़ताल की. □

एजेंट व वार्षिक ग्राहक ध्यान दें

साथी एजेंटों से हमारा अनुरोध है कि वे अपने बिलों का तुरंत भुगतान करें. ऐसा न करने से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. आशा है कि हमारे साथी एजेंट बिलों का तुरंत भुगतान करके प्रकाशन की सहायता करेंगे.

जिन वार्षिक ग्राहकों ने अपने चंदे का नवीकरण नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे शीघ्र ही इसका नवीकरण करा लें.

—मैनेजर

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के सम्मेलन द्वारा हड़तालो कार्यवाही का आह्वान

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) के 25 दिसंबर को कलकता में संपन्न 43वें वार्षिक सम्मेलन ने पश्चिम बंगाल के 25 लाख जूट मजदूरों का आह्वान किया है कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताली कार्यवाही के लिए तैयार रहें. अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले चेतावनी देने के लिए एक दिन की हड़ताल फरवरी महीने में की जाएगी, इनकी तारीख अन्य यूनियनों के साथ मिलकर तय की जाएगी. राज्य के सभी 62 जूट मिलों से एक हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. बी सी एम यू के अध्यक्ष नीरेन घोष ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे से शुभकामना-संदेश प्राप्त हुआ था.

बी सी एम यू के महासचिव कमल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में संकेत किया कि आई जे एम ए के नेतृत्व में मिल मालिकान किस प्रकार लगातार 1979 के त्रिपक्षीय समझोते का उल्लंघन कर रहे हैं और ग्रेड्स व स्केल कमेटी की सिफारिशों पर राज्य के श्रम मंत्री के फैसले को मानने से इंकार कर रहे हैं. हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में हार जाने के बाद भी मालिकान ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है. आई जे एम ए ने मजदूरों के साथ टकराव की नीति अपना ली है. लाकआउट की धमकी देकर हर मिल में कार्यभार बढ़ाया जा रहा है और एक विभाग से दूसरे विभाग में मनमाने ढग से तबादले किए जा रहे हैं. समझौते का उल्लंघन करते हुए मजदूरों का मकान किराया काटा जा रहा है और कैन्टीन राहत कम की जा रही है. अनेक मिलों में 90 प्रतिशत स्थायी व 20 प्रतिशत विशेष बदली का समझौता लागू नही किया जा रहा है. मजदूरों के वेतन से काटी गई प्रोविडेट फंड व ई एस आई राशि का करोड़ों रुपया जमा नही कराया गया. आई जे एम ए ने 20 प्रतिशत बोनस की मांग की अपेक्षा मात्र 8.33 प्रतिशत देने का प्रस्ताव रखा और वह भी किस्तों में. रिर्पोट में यह भी बताया गया कि मिल मालिकान ने भारत सरकार व रिजर्व बैंक से 111 करोड़ रुपयों की राहत व ऋण प्राप्त करने के बाद भी धन की कमी के बहाने से कच्चा जूट खरीदने से इंकार करके लाखों जूट उत्पादकों को असहाय बना दिया है. आठ जूट मिल या तो बंद हैं या उनमें लाकआउट है

रिपोर्ट में भारत सरकार की मिल मालिकान को, जो सैकड़ों करोड़ रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं, और उसे विभिन्न राज्यों में दूसरे उद्योगों में लगा रहे हैं, समर्थन देने पर कड़ी आलोचना की गई. रिपोर्ट कहती है कि जूट सामंतों की लूट से उद्योग को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि कच्चे जूट व जूट उत्पादों सहित समूचे जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए.

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें मजदूरों का आह्वान किया गया है कि फरवरी में एक दिन की चेतावनी हड़ताल करें और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहें.

सम्मेलन ने एक नया दस-सूत्री मांग पत्र बनाया क्योंकि 1979 का समझौता 31 दिसंबर को समाप्त हो गया है. अन्य यूनियनों के साथ बातचीत करके मांगपत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा और मालिकान को दे दिया जाएगा. मांगों पर संघर्ष कार्यक्रम भी इसमें तैयार किया गया.

इससे पहले, सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सी पी आई (एम) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव प्रमोद दास गुप्त ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद जो 1930 के बाद सबसे घने संकट में फंसा है, दलदल से निकलने के लिए एक और युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है. अमरीका ने बड़े पैमाने पर न्यूट्रान बमों के निर्माण का आदेश दे दिया है और इसका खास निशाना है सोवियत यूनियन व समाजवादी देश. आंतरिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के पूंजीवादी रास्ते ने देश को ऐसे ही संकट में डाल दिया है और अपने आप को इससे निकालने के लिए कांग्रेस (आई) सरकार आई एम एफ के समक्ष देश की आर्थिक स्वतंत्रता को समर्पित कर रही है जिससे संकट और गहराएगा जिसका भार मजदूरों और आम जनता पर डाल दिया जायगा. बढ़ते विरोध को दबाने के लिए इंदिरा गांधी एक के बाद एक अधिनायकवादी कदम उठा रही है. एन एस ए, एस्मा सरकार के अधिनायकवादी चरित्र के चिन्ह हैं. उन्होंने जूट मजदूरों का आह्वान किया कि वे 19 जनवरी की हड़ताल को सफल बनाने के लिए देश के मजदूर वर्ग के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें

जिन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया उनमें राज्य श्रम मत्री कृष्णपद घोष, सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय, राज्य परिवहन मंत्री मुहम्मद अमीन आदि शामिल हैं.

सम्मेलन ने एकमत से नीरेन घोष को अध्यक्ष तथा कमल सरकार को महासचिव चुना. 175 सदस्यीय नयी केंद्रीय कार्यकारी समिति में श्री गंगाम्मा उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हैं. □

अगले अंक में

जब यह अंक प्रैस में था, उस समय किन्हीं कारणों से लेख 'आई एल ओ कमेटी : बागान संबंधित कार्य' रोक लिया गया. यह लेख अब आगामी अंक में प्रकाशित होग—सं.

एच एस सी एल यूनियनों का अखिल भारतीय सम्मेलन

एच एस सी एल यूनियनों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दुर्गापुर में 7 जनवरी को संपन्न हुआ. इसने एच एस सी एल यूनियनों की गतिविधियों की समीक्षा की और वेतन समझौते व सेवा सुरक्षा के लिए एच एस सी एल मजदूरों के एकजुट आंदोलन को मजबूत करने का फैसला लिया.

सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय ने झंडा फहराया और प्रतिनिधियों ने शहीद स्तंभ पर फूल चढ़ाए.

सम्मेलन ने कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्षमंडल चुना जिसके सदस्य थे के. पी. घोष, बिनोय लाहिरी और पी. के. मुखर्जी.

स्वागत समिति के अध्यक्ष रोबिन सेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मनोरंजन राय ने एच एस सी एल मजदूरों का एकजुट संघर्षों में आगे रहने के लिए आह्वान किया. संयोजक एस एल बोस ने फिर कोआर्डिनेशन कमेटी की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. इसमें बताया गया कि निर्माण उद्योग में मजदूरों की क्या स्थिति है और किस प्रकार सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में प्रबंधक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं. इसमें जोर दिया गया कि एच एस सी एल प्रबंधकों को मजदूरों की मांगें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए और अधिक एकजुट संघर्षों की जरूरत है.

रिपोर्ट पर बोलते हुए कई वक्ताओं ने उन द्वारा चलाए गए स्थानीय संघर्षों के अपने अनुभवों को बताया. उन्होंने प्रबंधकों के हाथों को मजबूत करने में इंटक की विश्वासघाती भूमिका की भी आलोचना की.

सम्मेलन ने एस्मा तथा एच एस सी एल प्रबंधकों की छटनी की नीति के खिलाफ प्रस्ताव अपनाए. एक और प्रस्ताव द्वारा इसने मजदूरों के गुप्त-मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता देने की मांग की. सम्मेलन ने आई एम एफ ऋण की शर्तों और उनका भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की निंदा की. इसने फिर समूचे निर्माण उद्योग में मजदूरों की मांगों का समर्थन किया.

सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी के सचिव शांति घटक ने सम्मेलन का अभिनंदन करते हुए एच एस सी एल मजदूरों से अपील की कि देश में निर्माण मजदूरों के एक शक्तिशाली आंदोलन के निर्माण में अगुवा भूमिका अदा करें.

सीटू सचिव एम के पंधे ने बहस का समापन करते हुए एच एस सी एल यूनियनों का संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया ताकि एच एस सी एल प्रबंधकों की नीतियों के खिलाफ और भी अधिक दृढ़ संकल्पी संघर्ष चलाया जा सके. □

ग्रामीण असंगठित श्रम पर

ग्रामीण असंगठित श्रम पर सेंट्रल स्टेंडिंग कमेटी की एक बैठक 12 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई. इसमें सीटू का प्रतिनिधित्व नृसिंह चक्रवर्ती ने किया.

इसकी 8 जुलाई 1981 को संपन्न बैठक के बाद सरकार ने बांडेड, माइग्रेंट व आकस्मिक श्रम पर, जिसका काम पहले यही कमेटी करती थी, एक और कमेटी बना दी.

बैठक की कार्यसूची में बीड़ी, हैंडलूम व चमड़ा उद्योग व मजदूरों के हालात पर विचार करना था. सीटू प्रतिनिधि ने बताया कि मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और असंगठित है, तो भी ये उद्योग हैं. इस तथ्य के कारण कि ये मजदूर बिखरे हैं इसके परिणामस्वरूप उनका उद्योगपतियों द्वारा, खास तौर से दलालों द्वारा, शोषण किया जा रहा है. यह सुझाव दिया गया कि ऐसा शोषण कम किया जा सकता है यदि इन बिखरे मजदूरों को उचित दामों की गारंटी के लिए सरकार खरीद-एजेंसियां बना दे. कुछ अन्यों ने सहकारी समितियां बनाने का सुझाव दिया जो कुछ राज्यों में इन मजदूरों के हालात में सुधार लाने में कामयाब रहीं.

सीटू प्रतिनिधि ने संकेत किया कि पहले ही बीडी मजदूरों के कल्याण के लिए एक कमेटी है और इन कमेटियों को विपरीत लक्ष्यों के लिए काम नहीं करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि सरकार ने आई एल ओ की कनवेशन जो संगठन के अधिकार (कृषि) से संबधित है को अपनाया है फिर भी यह खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक कानून लाने में नाकामयाब रही है. उन्होंने फिर यह बताया कि सरकार ने आई एल ओ की कनवेंशन न० 95, 129 व 131 को अभी तक अपनाया नहीं है. इनमें श्रमनिरीक्षण से संबधित कनवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है. गुप्तमतदान द्वारा मजदूरों के इंस्पैक्टर नियुक्त होने पर न्यूनतम वेतन व अन्य कानूनों को लागू करने के लिए एक मशीनरी तैयार करना संभव हो जाएगा. इस विचार का समर्थन अन्य सदस्यों ने भी किया.

हालांकि श्रम राज्य मंत्री, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ने आश्वासन दिया कि खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतनों में संशोधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, सीटू प्रतिनिधि ने कहा कि ये संतोषजनक नहीं है.

श्रम उपमंत्री ने समुद्री मछेरों के हालात के मुद्दे को उठाया और सीटू प्रतिनिधि ने बताया कि केरल में एल डी एफ सरकार ने उनके लिए ग्रुप इंशोरेंस स्कीम सहित कई कदम उठाए हैं. ऐसे कदम अन्य राज्यों में भी उठाए जा सकते हैं. इस विचार की भी प्रशंसा की गई □

गणतंत्र दिवस के लिए एक विचार

स्वतंत्रता के तीन दशकों के बाद भी अमीर और गरीब के बीच अंतराल और आगे बढ़ा है. गरीबी रेखा के नीचे जनता में भी वृद्धि हुई है. यह बुनियादी भूमि सुधारों के प्रति लगातार हिचकिचाहट तथा हमारी अर्थव्यस्था पर एकधिकारी पूंजी की जबरदस्त जकड़ के कारण है. पूंजीवादी देशों से लिया गया हमारा ऋण हमारी आर्थिक स्वतंत्रता को धमकी दे रहा है.

हमारे देश में सामाजिक-आर्थिक पतन के वातावरण में राष्ट्र की एकता खतरे में है, साम्राज्यवादी स्वार्थों की शह पर विभिन्न धर्मों व जातियों, पृथकतावादी ताकतों, संप्रदायवाद तथा क्षेत्रीयतावाद के नेतृत्व में लोग टोह में हैं.

भारत में संसदीय जनवाद खतरे में है. अधिनायकवादी शासन की स्थापना की कोशिशों में कामकाजी जनता, ट्रेड यूनियनों के जनवादी अधिकारों तथा मत के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है. कानूनी प्रणाली व संविधान में फेरबदल करने की कोशिशें भी प्रतीत होती हैं. विपक्ष के सभी मतों को दबाने के प्रयास जारी हैं.

गणतंत्र दिवस पर आओ यह संकल्प करें : हमारी आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता व जनवाद की रक्षा के लिए आओ हम इन सभी बेलगाम ताकतों के खिलाफ सतर्क तथा स्पष्ट रहें.

पश्चिम बंगाल सरकार

नं० 314 (3)/आई सी ए

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डीए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित